

5. बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर द्वारा सन 1950 में ही महाराष्ट्र, कर्णाटक, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना राज्य में परम्परागत रूप से घंटी-भिक्षा व्यवसाय करने वाली जंगम जाति को बेड़ा जंगम, बूड़गा जंगम व माला जंगम के नाम से आरक्षण दिया गया है।

महोदय, उपरोक्त तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए मैं भारत सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि उत्तर भारतीय राज्यों विशेषकर हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू-कश्मीर की जंगम जाति को राष्ट्रीय घुमन्तू जनजाति आयोग (इदायते आयोग) की सिफारिश को लागू करते हुए पिछड़े वर्ग (बीसी) की सूची से हटाकर अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribes) की सूची में आरक्षण प्रदान करने की कृपा करें, धन्यवाद।

Concern over non-availability of records for 1962, 1965 and 1971 wars with National Archives of India

SHRI BRIJLAL (Uttar Pradesh): Sir, it has been gathered that non-historical records — since 1960 — and records of 1962, 1965 and 1971 Wars, and also the records on Green Revolution, are not available with the National Archives of India, as most of the departments have not shared the information for these years with the NAI. Sir, nine departments, Commissions, institutions and attached bodies, including Agriculture, IT and Electronics, Social Justice, Panchayati Raj, Rural Development, Women, Child Development and Child Affairs are some of the prominent departments/organizations yet to share the records with the NAI.

There are 151 Ministries and Departments, but NAI has records of only 64 agencies, including 36 Ministries and Departments.

Situation seems to be alarming and immediate steps need to be taken so that historically important information is not lost in the name of weeding out records. Officers and staff need to be sensitized about the awareness of records of historical importance and transfer it to NAI in a time-bound manner. Necessary instructions should immediately be sent to all Government organizations to identify, preserve and transfer this historical treasure trove to NIA.

Demand for establishment of Vidhan Parishad in Odisha

DR. SASMIT PATRA (Odisha): In August 2018, the Odisha Cabinet approved a proposal to set up a Vidhan Parishad or Legislative Council as an Upper House to the Odisha Vidhan Sabha or Legislative Assembly. Its strength would not exceed one-third of that of the Assembly, which in Odisha's case would work out to a maximum of 49 Members. The setting up of an Upper House was preceded by the setting up of a

Committee of Legislators in 2015. As the idea gained momentum, the Committee that had travelled to Karnataka and Maharashtra in 2015, and Telangana and Bihar in 2018 and, thereafter, submitted its report in the same year. In September 2018, the Odisha Vidhan Sabha passed a resolution to set up the Legislative Council or Vidhan Parishad in Odisha. The Resolution now needs the approval of the Union Cabinet, after which it would be tabled in both the Houses of Parliament and thereafter Presidential assent is required to make it an Act. There is a need to have a Vidhan Parishad in Odisha for extensive discussion and wider consultation on crucial issues pertaining to the State. Also, Bills, which are passed in the State Assembly, can have elaborate discussions in the Upper House. I request the Government of India to take all necessary steps for the establishment of the Odisha Vidhan Parishad expeditiously.

Faulty design of underpass situated under National Highway and Railway Line

श्री रामचंद्र जांगड़ा (हरियाणा) : मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को सदन के ध्यान में लाना चाहता हूँ।

मान्यवर, 2014 के बाद, जब से प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केन्द्र में सरकार बनी है, देश के आधारभूत ढांचे के विकास में नई क्रांति आई है। राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण हो, रेलवे नेटवर्क का विस्तार हो या हवाई यात्राओं व हवाई अड्डों की वृद्धि का विषय हो, हमारे देश ने मोदी जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व प्रगति की है। मान्यवर, आवागमन के मामले में हर भारतवासी को 2014 के बाद से हर क्षेत्र में अपार सुविधाएं मिली हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र से गुजरने वाले राजमार्गों व रेलमार्गों के कारण ग्रामीणों को कुछ कठिनाइयाँ झेलनी पड़ रही हैं। मैं आपके माध्यम से यह सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूँ।

मान्यवर, राष्ट्रीय राजमार्गों व रेलवे लाइनों के नीचे से गुजरने के लिए बने अंडरपासों की डिजाइनिंग काफी जगहों पर सही नहीं है। वे या तो बहुत गहरे हैं, जहाँ बारिश के दिनों में पानी भर जाता है और कुछ में तो 12 महीने जमीन के नीचे का पानी भरा रहता है, जिससे ग्रामीणों को काफी लंबा चक्कर लगाकर आना-जाना पड़ता है। कुछ इतने संकरे हैं कि आज के समय किसानों द्वारा प्रयोग की जाने वाली ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ उनमें से नहीं निकल सकतीं। इससे किसानों को बहुत कठिनाइयाँ होती हैं।

मान्यवर, मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि अंडरपासों की डिजाइनिंग के सुधारीकरण की ओर ध्यान दिया जाए तथा जो सही नहीं हैं, उनको सुधारा जाए।

Demand to develop Hapur as Spiritual city

श्रीमती कान्ता कर्दम (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं आज इस सदन का ध्यान हापुड़ जिले में विकास की महत्वपूर्ण संभावनाओं की ओर आकर्षित करने के लिए खड़ी हुई हूँ। उत्तर प्रदेश में स्थित हापुड़ में पवित्र स्थलों और आकर्षणों की एक विविध श्रृंखला है, जो इसे गहन सांस्कृतिक और